डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 16 अप्रैल, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 अप्रैल, 2025

| वर्ष 68 | अंक 22 | भोपाल | 16 अप्रैल, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश, प्राथमिक साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन में देश में प्रथम: केंद्रीय मंत्री श्री शाह

सहकारी समितियां अब टिकट बुकिंग, बिल जमा करने, पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी चलाने जैसी गतिविधियां भी करेंगी संचालित

प्रदेश में सुशासन के चलते, सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर

प्रदेश के किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है श्री मोदी सरकार

सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय किसानों के खातों में आएगी: मुनाफा किसानों को मिलगा, व्यापारी को नहीं

केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारी आंदोलन में आया क्रांतिकारी परिवर्तन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रदेश के 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता ओर डेयरी गतिविधियों का विस्तार आवश्यक

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य सहकारिता अनुबंधों का हुआ आदान-प्रदान

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन

भोपाल : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स) के कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसमें मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश में शत-प्रतिशत उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में साढ़े 5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जो देश के कुल उत्पादन का 9 प्रतिशत है। प्रदेश में सुशासन का दौर चल रहा है, यह सहकारिता को जीवंत करने का स्वर्णिम अवसर है। प्रदेश के किसानों के साथ केन्द्र सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर कम से कम 50 प्रतिशत गांवों तक सहकारिता और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक नीति निर्माण और प्लानिंग भी करना होगी। केन्द्र सरकार की ओर से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को दुग्ध उत्पादन का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित करनी होंगी। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग से विभिन्न उत्पाद निर्मित कर किसानों की आय बढ़ाने की ओर एनडीडीवी और राज्य सरकार एक साथ अग्रसर होंगे। यह रास्ता अभी टू-लेन है, जिसे 6 लेन में विस्तारित करना होगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह रविवार को भोपाल के रविन्द्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान हुआ।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि देश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े तीन साल में सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पैक्स के सशक्तिकरण, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहन, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता, गतिविधियों के विस्तार, नगरीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू संचालन की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय

सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद सबसे पहले प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के लिए मॉडल बायलॉज विकसित कर उन्हें राज्यों के साथ साझा किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि संपूर्ण भारत में यह बायलॉज को लागू किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने मॉडल बायलॉज को अपनाने के लिए सभी राज्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से सहकारिता आंदोलन को नया जीवन प्राप्त हुआ है। सहकारी समितियां अब पेट्रोल पम्प व गैस एजेंसी संचालन, रेल्वे टिकट बुकिंग, बिल जमा करने जैसी गतिविधियां भी संचालित कर रही हैं। एक समय था जब पैक्स केवल कम अवधि के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराते थे जिसमें उन्हें केवल आधा प्रतिशत लाभ होता था। वर्तमान में पैक्स 30 से अधिक गतिविधियों में संलग्न है इससे उनकी आय भी बढ़ रही है।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों में सहकारिता आंदोलन धीरे-धीरे मृत प्रायः होता जा रहा था। पूरे देश में सहकारिता आंदोलन का परिदृश्य भिन्न-भिन्न था। छः राज्यों में सहकारिता आंदोलन गति पर पकड़ चुका है, कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, परंतु कुछ जगह इसे नुकसान भी हुआ। इस स्थिति का मूल कारण यह था कि समय के साथ कानूनों में जो बदलाव होना चाहिए थे वे नहीं हुए। संवैधानिक व्यवस्था में सहकारिता राज्यों का विषय है, बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानून में बदलाव नहीं किया गया और न ही कानून बनाए गए। देश की राजनीतिक-भौगोलिक स्थिति, ग्रामीण, कृषि विकास और पशुपालन के आयाम पर समग्रता में केंद्रीय स्तर पर कभी विचार नहीं किया गया। यह संभव भी नहीं था, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर कोई सहकारिता मंत्रालय था ही नहीं। आजादी के 75 साल बाद, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को सशक्त करने के लिए त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति और डेयरी व मछुआरा गतिविधियों को जोड़कर एम-पैक्स बनाने का कार्य नए बायलॉज द्वारा संभव हो सका। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा 2500 करोड़ की राशि से सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया गया। अब पैक्स, जिला सहकारी बैंक, राज्य व सहकारी बैंक के साथ-साथ नाबार्ड से भी जुड़े हैं। इसके साथ ही इनके ऑनलाइन ऑडिट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषा में कार्य के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तीन नई किसान सहकारी समितियां का गठन किया गया। किसानों के उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में स्थान मिले, इसके लिए एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव बनाया गया, ऑर्गेनिक को-ऑपरेटिव का गठन किया गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से यह पहल की गई। यह दोनों संस्थाएं अगले 20 साल में अमूल से भी बड़ी संस्थाओं के रूप में आकर लेंगी। किसानों को बीज उत्पादन से जोड़ने के लिए बीच सहकारिता के अंतर्गत ढ़ाई एकड़ वाले किसानों को भी मान्यता दी गई। इन सहकारी गतिविधियों से होने वाली आय सीधे किसानों के खातों में आएगी उसका मुनाफा किसानों को मिलेगा, व्यापारी को नहीं। साथ ही सहकारिता में प्रशिक्षण के लिए सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि किसानों द्वारा खुले बाजार में दूध बेचने पर उचित दाम नहीं मिलता है अतः प्रत्येक गांव के किसानों को अधिक से अधिक संख्या में डेयरी के साथ जोड़कर दूध के विभिन्न उत्पाद निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा। दूध से दही, मट्ठा, छाछ, पनीर, चीज़ का निर्माण हो और इसका मुनाफा किसानों को मिले यह व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने, पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध के संकलन के लिए बेहतर नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। इन गतिविधियों में आज हो रहे अनुबंध महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए सहकारिता की गतिविधियां संचालित की जाएं : मुख्यमंत्री

कार्पोरेट संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार से करें सोसायटियों का सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 पर बैठक

मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय शीर्ष समिति को दिए निर्देश

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और सतत विकास में सहकारिता के योगदान के लिए ग्राम और वार्ड स्तर पर गतिविधियों का संचालन किया जाए। सहकारी सोसायटियों के सुदृढ़ीकरण के लिए नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए सहकारिता के सेट-अप में कार्पोरेट संस्कृति को विकसित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "ज्ञान पर ध्यान" के मंत्र को साकार करने और विकसित भारत के लिए भावी पीढ़ी की सहकारिता का आधार तैयार करने के उद्देश्य से गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से छूटे किसानों को चिन्हित कर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व, किसान कल्याण तथा एवं विकास, पशुपालन एवं डेयरी और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग समन्वित रूप से गतिविधियां संचालित करें। पैक्स के सशक्तिकरण और उन्हें अधिक समर्थ और सक्षम बनाने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय से कार्य किया जाए। शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस में पैक्स के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार की पहल पर वर्ष-2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। "सहकारिताएं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं" इसकी थीम है, जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सहकारी मॉडल की प्रभावशीलता को दर्शाती है। साथ ही यह वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के प्रयासों में सहकारिता के योगदान पर भी प्रकाश डालती है।

पराली न जलाएं किसान, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चलाएगा जागरूकता अभियान-प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टरेट की 169वीं बैठक में लिये गए निर्णय

भोपाल : प्रदेश में पराली जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के निदेशक मण्डल की 169वीं बैठक गुरवार को आयोजित की गई। बैठक में धान एवं गेहूं की कटाई के पश्चात जलने वाली पराली से होने वाले प्रदूषण पर गहन चर्चा हुई और इसके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता विभाग के प्रमुख सचिव एवं अध्यक्ष, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ने की।

प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने निर्देश दिये है कि प्रदेश में किसान पराली न जलाएं इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रमुख सचिव ने बताया कि इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया

जाएगा। इस अभियान के लिए 8 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने पराली के वैकल्पिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में स्थापित ताप विद्युत गृहों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिये है। बैठक में कटाई के बाद बचे बायोमास के वैकल्पिक उपयोग पर कार्ययोजना तैयार किये जाना का निर्णय लिया गया।

डॉ. कोठारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया है कि वायु गुणवत्ता और अन्य प्रदूषकों की सतत निगरानी के लिए 4 सुसज्जित मोबाइल मॉनिटरिंग वैन स्थापित की जाएगीं। साथ ही, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 100 और उससे अधिक तक की चिंताजनक स्थिति में जिन शहरों में पहुंच गई है, वहां 39 नए वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता के सतत मापन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 92 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख सचिव डॉ. कोठारी ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम प्रदेश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

सेवा सहकारी समिति छपारा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

सिवनी, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा दिनांक 07 अप्रैल 2025 को सेवा सहकारी समिति मर्यादित, छपारा जिला सिवनी में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य समिति के सदस्यों, संभावित सदस्यों तथा कर्मचारियों को सहकारी क्षेत्र से जुड़े प्रासंगिक विषयों एवं उनके कार्यों से संबंधित पहलुओं पर जागरूक करना एवं उनके कौशल का उन्नयन करना था।

शिविर में विशेषज्ञों द्वारा सहकारिता के सिद्धांत, समिति संचालन की प्रक्रिया, लेखा प्रबंधन, ऋण वितरण, वसूली प्रणाली, तथा पारदर्शिता बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे अपने कार्यक्षेत्र में इन जानकारियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकें।

प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अत्यंत उपयोगी बताते हुए इसे निरंतर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक : मुख्यमंत्री डॉ.यादव

जून 2025 तक सभी समितियों का ऑडिट सुनिश्चित किया जाए

मुख्यमंत्री ने दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों का कम्प्यूटराईजेशन करने के दिए निर्देश

समितियों के पारम्परिक गतिविधियों के साथ-साथ एग्रीड्रोन, जन औषधी केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर जैसी गतिविधियां संचालित की जाएं

सहकारिता क्षेत्र में पीपीपी मोड से व्यवसाय के नए अवसर खोजें

ड्रिप-एरीगेशन, ग्रेडिंग-सार्टिंग और पैकेजिंग, जंगल सफारी व गेस्ट हाउस, खाद्य प्र-संस्करण जैसी गतिविधियां को करें प्रोत्साहित

वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण किया वितरित

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सहकारी समितियों की साख और जन सामान्य में उनके प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए समितियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अत: सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यों का शत प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जून 2025 तक समितियों का ऑडिट पूर्ण कर कृषकों को लेन-देन की सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराने और इस वर्ष के अंत अर्थात दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देशित कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अल्पसेवित पंचायतों की पहचान कर नवीन सहकारी समितियों के गठन के लिए प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाए। वर्तमान परिदृश्य और आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक से अधिक समितियों में पारंपरिक गतिविधियों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, जल कर वसूली केंद्र और एग्री ड्रोन संचालन जैसी गतिविधियां चलाई जाएं। इसके साथ ही को-ऑपरेटिव- पब्लिक- प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) के माध्यम से सहकारी-सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता में नवाचार करते हुए ड्रिप एरीगेशन, ग्रेडिंग-सार्टिंग और पैकेजिंग, जंगल सफारी, गेस्ट हाउस और खाद्य प्र-संस्करण जैसी गतिविधियां को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जनकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 1286 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों क्रमश: खण्डवा, बड़वानी, गुना, राजगढ़, विदिशा, दमोह, छतरपुर और सिंगरौली में आगामी पांच वर्ष 6710 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश के 13 आकांक्षी विकास खण्डों में विभिन्न गतिविधियों पर आधारित 26 सहकारी समितियां गठित की गई हैं। जिला बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आईबीपीएस मुम्बई के माध्यम से अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत 36 अधिकारियों और 1358 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। जिला सहकारी बैंकों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।

महिलाओं हेतु सहकारी समिति गठन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

इंदौर। अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सहकारिता के महत्व, इसके लाभों एवं सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया से अवगत कराना था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विशेषज्ञों द्वारा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, पंजीयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें, वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के तरीके तथा समिति संचालन की रणनीतियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान सफल महिला सहकारिता नेताओं द्वारा अपने अनुभव साझा किए गए, जिससे प्रतिभागियों को प्रेरणा मिली। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी भी दी गई, जैसे कि समिति के लिए प्रस्ताव तैयार करना, बैठकें संचालित करना, और खातों का लेखा-जोखा रखना। साथ ही, यह भी बताया गया कि किस प्रकार सहकारी समितियाँ महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम बन सकती हैं। इस अवसर पर महिलाओं को आश्वस्त किया कि शासन स्तर से उन्हें पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं ने सहकारी समितियाँ गठित करने की इच्छा जताई और इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने का संकल्प लिया।

IFFCO कलोल इकाई का स्वर्ण जयंती समारोह एवं बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना : भारत की सहकारी क्रांति को नई दिशा

गांधीनगर, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित IFFCO की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया और साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल के तहतबीज अनुसंधान केंद्रकी आधारशिला भी रखी। इस समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

IFFCO की 50 वर्ष की उपलब्धियां और सहकारिता की शक्ति

श्री अमित शाह ने IFFCO की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्था सहकारिता और कॉर्पोरेट मूल्यों के समन्वय का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि IFFCO ने रिसर्च, ब्रांडिंग, विपणन और देश के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बनाकर किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

IFFCO द्वारा विकसितनैनो यूरियाऔरनैनो डीएपीने न केवल भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन दिया है, बल्कि विश्वस्तर पर भारत के सहकारी मॉडल को प्रतिष्ठा दिलाई है।

बीज अनुसंधान केंद्र: किसानों की समृद्धि का नया अध्याय

IFFCO द्वारा स्थापित किए जा रहे बीज अनुसंधान केंद्र को लेकर श्री शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि यह केंद्र किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, पोषण तत्वों से भरपूर बीज विकसित करने, कम पानी और कम उर्वरक में बेहतर फसल देने वाले बीजों के शोध को बढ़ावा देगा। इसके साथ-साथ, यह केंद्र पारंपरिक बीजों के संरक्षण का भी कार्य करेगा।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकारिता क्षेत्र में किए गए 62 अभूतपूर्व सुधारों की चर्चा करते हुए बताया कि सहकारी आंदोलन के अग्रदूत त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। यह विश्वविद्यालय पैक्स से लेकर एपेक्स स्तर तक आधुनिक कोऑपरेटिव शिक्षा, पारदर्शिता और AI जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने का कार्य करेगा।

IFFCO की उत्पादन शक्ति और वैश्विक उपस्थिति

IFFCO वर्तमान में कंडला, कलोल, फूलपुर, आंवला और पारादीप में स्थित पांच इकाइयों से देशभर में खाद्य उत्पादन में योगदान दे रहा है। आज इसकी उत्पादन क्षमता 90 लाख मीट्रिक टन तक पहुँच चुकी है, जबकि वार्षिक बिक्री 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। संगठन का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपये और लाभ 3,200 करोड़ रुपये से अधिक है।

IFFCO ने पिछले पांच दशकों में रासायनिक उर्वरकों से लेकर जैविक एवं नैनो तकनीक आधारित उर्वरकों की दिशा में जो यात्रा तय की है, वह कृषि में क्रांति के समान है। अब संस्था टारगेटेड और कंट्रोल रिलीज फर्टिलाइज़र की दिशा में कार्य कर रही है जिससे पोषक तत्वों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित हो रही है और जमीन की गुणवत्ता भी बनी रह रही है।

आगामी 50 वर्षों की दिशा

श्री शाह ने कहा कि IFFCO की अगली 50 वर्ष की यात्रा भारतीय खेती को आधुनिक, टिकाऊ, पर्यावरण-संवेदनशील और उच्च उत्पादकता युक्त बनाने के चार उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ेगी। बीज अनुसंधान केंद्र और सहकारी विश्वविद्यालय जैसे प्रयास किसानों की समृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए मील का पत्थर सिद्ध होंगे।

युवाओं को सहकारिता से जोड़ने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

नौगांव,अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा दिनांक 3 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), नौगांव के परिसर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी प्रदान करना था।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केंद्र एवं RSETI के स्टाफ सदस्यों सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता के सिद्धांत, संरचना, योजनाएं तथा स्वरोजगार की संभावनाओं पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए प्रतिभागियों ने इसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित विषयवस्तु पर आधारित अध्ययन सामग्री (नोट्स) भी वितरित की गई।

सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। आयोजनकर्ताओं ने आशा व्यक्त की कि इससे युवाओं में सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और वे भविष्य में इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा उमरानाला में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

जबलपुर: सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को सेवा सहकारी समिति मर्यादित उमरानाला, जिला छिंदवाड़ा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।इस प्रशिक्षण शिविर में समिति के प्रबंधक श्री प्रशांत लाडे, लेखापाल विनोद गायकवाड़, विक्रेता शिवलाल, हेमंत, कंप्यूटर ऑपरेटर पवन शुक्ला, भ्रत्य दशरथ पवार सहित समिति के अन्य सदस्य एवं ग्राम के कृषक बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

शिविर का उद्देश्य सहकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना था, जिनमें समिति संचालन, सदस्यता प्रक्रिया, आर्थिक प्रबंधन, तकनीकी दक्षता एवं साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रमुख रही।प्रशिक्षण में विशेष रूप सेसायबर अपराधों की बढ़ती घटनाओंएवं उनसे बचाव के उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल व्यवहार में सुरक्षा उपायों जैसे मजबूत पासवर्ड, ओटीपी की गोपनीयता, संदिग्ध लिंक से बचाव आदि के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कृषकों व समिति सदस्यों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी व ज्ञानवर्धक बताया तथा भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की अपेक्षा जताई।सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समितियों की कार्यक्षमता एवं कृषकों की जागरूकता बढ़ाने का सतत प्रयास किया जा रहा है।

सुजानपुरा में दुग्ध सहकारी समिति हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग सम्पन्न

टीकमगढ़, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव द्वारा दिनांक 27 मार्च 2025 को बुन्देलखण्ड दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, सुजानपुरा, जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय दुग्ध उत्पादक किसानों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम का उद्देश्य समिति से जुड़े सभी हितधारकों को दुग्ध सहकारी प्रणाली की बेहतर समझ देना तथा आधुनिक तकनीकों एवं कार्यप्रणालियों से अवगत कराना था।

प्रशिक्षण के दौरान सहकारी सिद्धांतों, समिति की संरचना, उसकी जिम्मेदारियों और पारदर्शी संचालन पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि सहकारी समितियाँ केवल उत्पाद एकत्र करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का एक सशक्त उपकरण हैं।

प्रमुख प्रशिक्षण विषयों में शामिल रहे:

- दुग्ध संग्रहण की वैज्ञानिक विधियाँ
- गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण की प्रक्रिया
- पशुपालन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें
- चारा प्रबंधन, टीकाकरण एवं पशु स्वास्थ्य सुरक्षा
- सहकारी संस्था का लेखा-जोखा और लाभ वितरण
- सदस्यों की जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सहभागिता

प्रशिक्षकों ने यह भी बताया कि गुणवत्ता युक्त दूध उत्पादन, समय पर संग्रहण और उचित विपणन से समिति की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे सभी सदस्यों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने डिजिटल तकनीक, दूध परीक्षण यंत्रों और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे आधुनिक उपायों की जानकारी भी दी।

सदस्यों ने प्रशिक्षण को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें अपने कार्य में न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगी, बल्कि समिति को भी अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाएंगी।

कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव एवं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी इस प्रकार के उपयोगी प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की अपेक्षा जताई।

महिलाओं को सहकारी समिति गठन हेतु किया गया प्रेरित, जबलपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

जबलपुर,अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें संगठित कर सहकारी समितियों के गठन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से जबलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जबलपुर शहर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रतिभागियों को सहकारी समितियों की स्थापना प्रक्रिया, प्रबंधन कौशल, वित्तीय लाभ, कानूनी प्रक्रियाएं तथा समितियों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। विषय विशेषज्ञों ने सहकारी समितियों को महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बताते हुए उनके सामाजिक व आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने इस प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। कई प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में

सहकारी समिति गठन की इच्छा जताते हुए इसे आजीविका का बेहतर माध्यम माना।

वनोपज सहकारी समिति गोभा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

सिंगरौली, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा दिनांक 29 मार्च 2025 को वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, गोभा, जिला सिंगरौली में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष श्री श्यामदास केवट, समिति के अन्य सदस्य, कर्मचारी एवं संभावित सदस्य उपस्थित रहे।

शिविर में वनोपज से जुड़ी विविध जानकारियाँ, समिति के संचालन की प्रक्रिया, तथा सदस्यों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को वनों से प्राप्त उपयोगी उत्पादों, उनके संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की तकनीकों से अवगत कराया गया।

प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि वनोपज वे उपयोगी उत्पाद होते हैं जो वनों से लकड़ी के अलावा प्राप्त होते हैं। इनमें प्रमुख रूप से तेंदूपत्ता, महुआ फूल एवं बीज, हर्रा, बहेरा, आंवला, गोंद, शहद, लाह, चिरौंजी और बांस शामिल हैं। ये उत्पाद वनवासी एवं आदिवासी समुदाय की आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

शिविर के दौरान सहकारी सिद्धांतों, पारदर्शिता, लेखा प्रक्रिया, तथा समिति संचालन के व्यावहारिक पहलुओं पर भी प्रशिक्षण दिया गया। सहभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों की नियमितता की आवश्यकता पर बल दिया।

वारासिवनी में बांस शिल्प प्रशिक्षण सम्पन्न

वारासिवनी। वृहंत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (बांस शिल्प) का आयोजन 06 फरवरी 2025 से 05 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा वारासिवनी, जिला बालाघाट में किया गया।

इस दो माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर श्री रमेश कुरेले द्वारा प्रतिभागियों को बांस शिल्प से जुड़ी पारंपरिक एवं आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बांस से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे टोकरी, पंखा, दीपक, लैंप शेड, बांस की बोतलें, शोपीस, कुर्सी-टेबल जैसे फर्नीचर, स्टेशनरी आइटम और कृषि उपयोगी उपकरण तैयार करना सिखाया गया। साथ ही उत्पादों की डिज़ाइनिंग, फिनिशिंग, ब्रांडिंग और बाजार में बिक्री से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाना एवं पारंपरिक बांस शिल्प को प्रोत्साहन देना रहा। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में स्थानीय प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसे रोजगार के नए अवसर के रूप में सराहा।

डॉ. सुवा कांत मोहंती ने वामनिकॉम के निदेशक पद का कार्यभार संभाला

सहकारिता शिक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक नया कदम

पुणे, वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वामनिकॉम), पुणे में आज एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत डॉ. सुवा कांत मोहंती ने निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया। वे डॉ. हेमा यादव का स्थान ले रहे हैं, जिनके कार्यकाल में संस्थान ने सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई नवाचार किए।

डॉ. मोहंती एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् हैं और उन्हें शिक्षण, अनुसंधान तथा शैक्षणिक नेतृत्व के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनाइटेड किंगडम से एप्लाइड इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। यह अध्ययन उन्होंने CGIAR द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित GRiSP स्कॉलरशिप के अंतर्गत पूर्ण किया।

वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक पहलें की जा रही हैं। हाल ही में संसद में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक पारित हुआ है और साथ ही IRMA के उन्नयन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इन प्रयासों में वामनिकॉम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

डॉ. मोहंती इससे पूर्व कीट विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक के रूप में कार्यरत थे। साथ ही उन्होंने IRMA में एचडीएफसी चेयर प्रोफेसर, मार्केटिंग विभागाध्यक्ष, एसोसिएट डीन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उनकी विशेषज्ञता उपभोक्ता व्यवहार, रिटेलिंग और सेवाओं के विपणन जैसे क्षेत्रों में है।

यद्यपि डॉ. मोहंती का प्रत्यक्ष अनुभव सहकारी संस्थानों के साथ नहीं रहा है, परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था से उनके गहरे जुड़ाव और IRMA में उनके अनुभव को देखते हुए यह विश्वास जताया जा रहा है कि वे इस क्षेत्र को शीघ्रता से आत्मसात कर सकेंगे। उनकी तीन वर्षीय अनुबंधीय नियुक्ति को सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। उनके नेतृत्व में वामनिकॉम से नए आयाम स्थापित करने की आशा की जा रही है।

(पृष्ठ 1 का शेष) | **मध्यप्रदेश, प्राथमिक साख सहकारी समितियों...**

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री प्रबंधन में पारस की तरह

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह के कुशल प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि वे पारस की तरह हैं, उनके पास जो विभाग आ जाए वह "सोना" हो जाता है। उनकी उपस्थिति में हो रहे अनुबंध से प्रदेश में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। बहुउद्देशीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में भी सहकारिता की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है।

सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अब सहकारी समितियों से पेट्रोल पंप, दवाई की दुकान व अन्य गतिविधियां संचालित होंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में फैक्ट्रियों को भी सहकारिता से चलाने के लिए अनुबंध हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादन हर घर की आय में वृद्धि का प्रमाणिक स्त्रोत है। प्रदेश में गौ-पालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौ-पालन पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा है। सरकार घर-घर गोकुल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए सरकार गाय का दूध खरीदेगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी और श्री केन्द्रीय मंत्री श्री शाह के मार्गदर्शन में किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ प्रतिबद्ध है। वृहद स्तर पर एमओयू होने से आज बड़ी संभावनाओं का द्वार खुले है।

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए एतिहासिक है। राज्य सरकार ने सहकारिता के साथ निजी व शासकीय भागीदारी को जोड़ते हुए सी.पी.पी.पी. के माध्यम से पहली बार देश में नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सहकारिता को नए आयाम प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। पशुपालन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने अनुबंध की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री शाह ने आज अनुबंध के माध्यम से मध्यप्रदेश को नई सौगात दी है। डेयरी विकास में गुजरात में किए विकास कार्य मध्यप्रदेश को नई गति प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निदेशक डॉ. निमेश शाह ने कहा कि एनडीडीबी, मध्यप्रदेश सरकार और 6 दुग्ध संघ के बीच सहकार्य अनुबंध (एमओयू) हो रहा है। राज्य सरकार ने संगठित बोर्ड के माध्यम से दूध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुबंध की सहमति प्रदान की है। इस अनुबंध से किसानों को प्रशिक्षण देना, दूध उत्पादों की मार्केटिंग सहित अनेक कार्य किए जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी प्लान श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करना शामिल है। एनडीडीबी दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सी.पी.पी.पी. के अंतर्गत हुए अनुबंध

केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में सी.पी.पी.पी. के तहत मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक श्री विज्ञान लोढ़ा द्वारा पैक्स घाट पिपरिया जिला रायसेन के समिति प्रबंधक श्री भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्योरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिये अनुबंध का निष्पादन हुआ। इसके साथ ही मैसर्स मशरूम वर्ल्ड अम्ब्रेला लिमिटेड के प्रबंध संचालक श्री समीर सागर द्वारा पैक्स सलामतपुर जिला रायसेन के समिति प्रबंधक श्री कुँवर सिंह दांगी के साथ नेपियर घास के कल्टीवेशन के लिये अनुबंध हुआ। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कार्यक्रम में चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिये स्वीकृत ऋण पत्र भी वितरित किए। इसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिये 15 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला द्वारा पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिये 60 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांवा जिला खरगौन को सुपर मार्केट के लिये 120 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण प्रदान किया गया। दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी जिला भोपाल के सचिव श्री महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम और पैक्स सांकलखेड़ा खुर्द के कृषक श्री यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। पैक्स सुसनेर जिला आगर-मालवा के समिति प्रबंधक श्री पुष्पेन्द्र सिंह पेट्रोल पंप आवंटन का एलओआई दिया गया। साथ ही जन औषधि केन्द्र पैक्स कुआं जिला कटनी के समिति प्रबंधक श्री अजय कुमार नायक को ड्रग लाइसेंस प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल और अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री उमाकांत उमराव उपस्थित थे।

पारंपरिक जूट शिल्प को डिज़ाइन और ब्रांडिंग का नया रूप

भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा भारत सरकार की वृहंत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत पारंपरिक जूट शिल्प को आधुनिक डिज़ाइन, तकनीकी कौशल और बाज़ार की मांगों के अनुरूप उन्नत करने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में स्थानीय महिलाओं, युवाओं और शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे अपने शिल्प को व्यावसायिक पहचान दिला सकें।

पहला कार्यक्रम गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम (जूटशिल्प) 22 जनवरी से 21 मार्च 2025 तक रविशंकर नगर, भोपाल में संपन्न हुआ। इस दो माह के प्रशिक्षण का संचालन मास्टर ट्रेनर श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जूट शिल्प की पारंपरिक विधाओं को आधुनिक डिज़ाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने जूट से बैग, पर्स, टेबलमैट, फ्लावर पॉट कवर, गिफ्ट आइटम्स और सजावटी सामग्री जैसे आकर्षक उत्पाद तैयार किए। साथ ही उन्हें उत्पाद की डिज़ाइनिंग, रंग संयोजन, सिलाई तकनीक, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन संबंधी व्यावसायिक जानकारियाँ भी दी गईं।

दूसरा कार्यक्रम "डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला (जूटशिल्प)" 19 फरवरी से 20 मार्च 2025 तक पंचशील नगर, भोपाल में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का संचालन प्रसिद्ध डिज़ाइनर श्रीमती रूकमणी पंवार द्वारा किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य था जूट शिल्प को इस तरह डिज़ाइन और तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत करना कि उसके उत्पाद अधिक आकर्षक, उपयोगी और बाज़ार योग्य बन सकें। श्रीमती पंवार ने प्रतिभागियों को बताया कि किस प्रकार जूट उत्पादों की टिकाऊ और प्राकृतिक विशेषताओं को ब्रांड की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्यशाला में उत्पादों की आधुनिक डिज़ाइन, रंग संयोजन, गुणवत्ता मानक, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, और ई-कॉमर्स जैसे विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान हस्तशिल्प सेवा केंद्र, भोपाल के सहायक निदेशक श्री नरसिंह सैनी, विशेषज्ञ संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष राजपूत और राज्य सहकारी संघ की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान की विशेष उपस्थिति रही। श्री नरसिंह सैनी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि जूट शिल्प भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिल्पकारों को न केवल उनके कौशल को निखारने का अवसर देता है, बल्कि उन्हें बाज़ार की प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करता है।" प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान ने कहा कि जूट शिल्प के उत्पादों में अपार संभावनाएं हैं। यह कार्यशाला डिज़ाइन और विपणन के क्षेत्र में शिल्पियों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य संघ आगे भी इस तरह के आयोजन करता रहेगा।"

20 मार्च 2025 को कार्यशाला का समापन हुआ, जिसमें प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए जूट उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। बैग, पर्स, होम डेकोर आइटम्स, टेबल रनर, वॉल हैंगिंग्स, गिफ्ट आइटम्स और अन्य रचनात्मक उत्पादों को देखकर प्रतिभागियों के काम की खूब सराहना की। अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण करने के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। यह आयोजन शिल्पकारों के लिए एक बड़ा मंच बना, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास मिला।

यह संपूर्ण आयोजन पारंपरिक शिल्प की नवाचार के साथ पुनर्रचना का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। यह कार्यक्रम न केवल जूट शिल्प को नया स्वरूप देने में सफल रहा, बल्कि महिलाओं एवं युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हुआ है।

शिल्पकार का सशक्तीकरण-इंदौर में हुआ टूलकिट वितरण कार्यक्रम

इंदौर, भारत सरकार की वृहंत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के तहत कढ़ाई शिल्प से जुड़े कारीगरों को आत्मनिर्भर और दक्ष बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इस पहल के अंतर्गत दिनांक 8 अप्रैल 2025 को इंदौर के किला मैदान स्थित सामुदायिक सुविधा केंद्र (CFC) में टूलकिट वितरण कार्यक्रमका भव्य आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से शिल्पकारों को ऐसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए, जो उनकी कार्यक्षमता और उत्पादन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। वितरित टूलकिट में कढ़ाई कार्य के लिए आवश्यक उन्नत उपकरण, विविध प्रकार के धागे, डिज़ाइन फ्रेम, सुई सेट, माप यंत्र आदि शामिल थे।

कार्यक्रम में हस्तशिल्प सेवा केंद्र, इंदौर की सहायक निदेशक श्रीमती अर्पणा देशमुख, राज्य सहकारी संघ, इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमठ तथा विशेषज्ञ संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष राजपूत ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई।

श्रीमती अर्पणा देशमुखने अपने संबोधन में कहा: "कढ़ाई शिल्प केवल एक पारंपरिक कला नहीं, बल्कि वर्तमान में यह महिलाओं और युवाओं के लिए सशक्त आजीविका का साधन बन चुकी है। यह टूलकिट उन्हें न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि

आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा।"

श्री दिलीप मरमठने बताया: "इंदौर क्षेत्र में शिल्प प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की निरंतर श्रृंखला चलाई जा रही है। राज्य सहकारी संघ भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से शिल्पकारों को सहयोग करता रहेगा।"

श्री मनीष राजपूतने ज़ोर देकर कहा: "सिर्फ उपकरण देना ही पर्याप्त नहीं है। डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग और उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने की दिशा में भी हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हम शीघ्र ही इन विषयों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेंगे।" कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला और युवा शिल्पकारों ने सहभागिता की। टूलकिट प्राप्त कर उन्होंने प्रसन्नता और उत्साह व्यक्त किया। अनेक शिल्पकारों ने बताया कि यह सहयोग उनके लिए एक नई शुरुआत जैसा है, जिससे वे अपने हुनर को और निखारकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगे।कार्यक्रम का समापन सामूहिक छायाचित्र एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।यह आयोजन शिल्पकार समुदाय के सशक्तीकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक और प्रभावी कदम के रूप में चिह्नित किया गया।

किसान उत्पादक संगठन (FPO): ग्रामीण भारत की समृद्धि की चाबी

भारत के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत वर्ग से आते हैं, जिन्हें कृषि कार्यों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे किसानों को संगठित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिएकिसान उत्पादक संगठन (FPO) की अवधारणा लाई गई है। एफपीओ एक ऐसा संगठन होता है, जिसमें किसान मिलकर खेती से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करते हैं, जैसे– बीज खरीद, फसल विक्रय, भंडारण, प्रसंस्करण आदि। इसका उद्देश्य किसानों कीआय बढ़ाना, लागत घटानाऔरबिचौलियों की भूमिका कम करनाहोता है।

एफपीओ की नींव वर्ष 2002 में 'लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC)' के माध्यम से रखी गई। 2013 में इसे कानूनी मान्यता मिली और 2020 में सरकार ने "10,000 एफपीओ योजना" की शुरुआत की। आज भारत में दस हजार से अधिक एफपीओ कार्यरत हैं।

एफपीओ के लाभ

1. सस्ती कृषि सामग्री: सामूहिक रूप से बीज, खाद और मशीनें खरीदकर लागत घटाई जा सकती है।
2. बेहतर मूल्य: सामूहिक रूप से उपज बेचने पर उचित दाम मिलता है।
3. तकनीकी ज्ञान: आधुनिक खेती और जैविक पद्धतियों का प्रशिक्षण मिलता है।
4. सीधा बाजार संपर्क: एफपीओ खुदरा विक्रेताओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं।
5. जोखिम प्रबंधन: सामूहिक रूप से प्राकृतिक और आर्थिक जोखिमों से निपटा जा सकता है।
6. बुनियादी सुविधाएँ: एफपीओ

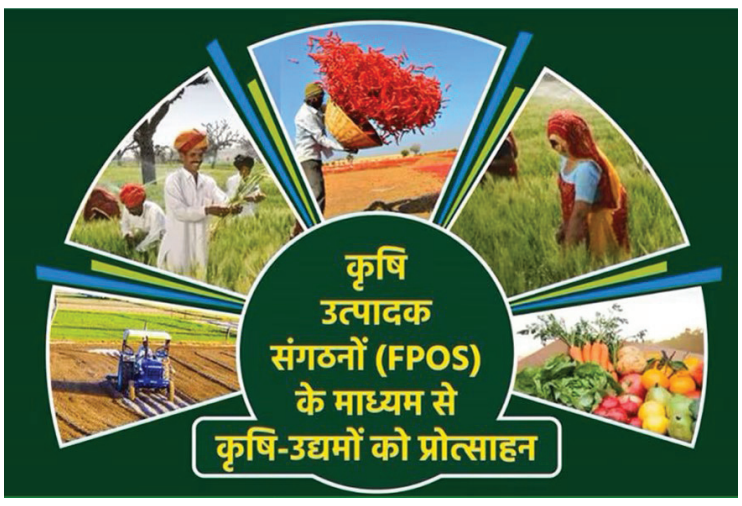

भंडारण, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सकते हैं।

चुनौतियाँ

1. बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।
2. नेतृत्व और प्रबंधन की कमी।
3. बाजार की जानकारी का अभाव।
4. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी।
5. पंजीकरण और नियमों की जटिल प्रक्रिया।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव।

सरकारी प्रयास

- SFACऔर NABARD एफपीओ को तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY)के तहत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान मिलता है।
- सरकार द्वारा ऋण गारंटी योजना चलाई गई है जिससे बैंकों से ऋण आसानी से मिल सके।

स्मार्ट एफपीओ क्या हैं?

स्मार्ट एफपीओ वे संगठन हैं जो डिजिटल तकनीक, ई-कॉमर्स, मोबाइल ऐप, डिजिटल भुगतान, और डेटा विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। ये पारंपरिक एफपीओ से अधिक दक्ष, पारदर्शी और किसानों के लिए लाभकारी होते हैं। इनसे किसानों को बाजार से सीधे जुड़ाव और बेहतर लाभ मिल सकता है।

आगे की राह

- एफपीओ को व्यवसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- आसान ऋण और अनुदान योजनाएँ लागू होनी चाहिए।
- डिजिटल तकनीक और स्मार्ट कृषि उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए।
- एफपीओ को पंजीकरण और नियमन में सरलता मिलनी चाहिए।

एफपीओ किसानों को संगठित करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हैं। स्मार्ट एफपीओ इस प्रयास को और गति दे सकते हैं। यदि सरकार, संस्थाएँ और किसान मिलकर कार्य करें, तो एफपीओ भारत की कृषि व्यवस्था को आत्मनिर्भर और समृद्ध बना सकते हैं।

भोपाल में पारंपरिक शिल्पों को नया जीवन : जूट, जरी-जरदोजी और कढ़ाई शिल्प पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

परंपरागत हस्तशिल्पों के संरक्षण और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

भोपाल, भारत सरकार की वृहंत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा तीन प्रमुख पारंपरिक शिल्पों – जूट शिल्प, जरी-जरदोजी एवं कढ़ाई शिल्प – पर आधारित गुरु-शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य शिल्पों को संरक्षित कर उन्हें व्यावसायिक स्वरूप देना तथा नवोदित शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना रहा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में महिला एवं युवा शिल्पियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान शिल्पकला के तकनीकी पक्ष के साथ-साथ डिज़ाइन इनोवेशन, उत्पाद गुणवत्ता, विपणन रणनीति और ऑनलाइन विक्रय की जानकारी भी दी गई।

जूट शिल्प प्रशिक्षण: टिकाऊ शिल्प के साथ रोज़गार के अवसर

गांधी भवन, भोपाल में 4 फरवरी से 3 अप्रैल 2025 तक आयोजित जूट शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को जूट बैग, वॉल हैंगिंग, सजावटी वस्तुएँ एवं गिफ्ट आइटम्स तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर श्रीमती नीतू यादव ने प्रतिभागियों को उत्पाद निर्माण के साथ-साथ डिज़ाइन, रंग संयोजन एवं गुणवत्ता नियंत्रण की तकनीकों से भी अवगत कराया।

जरी-जरदोजी शिल्प: परंपरा में नवाचार का समावेश

इसी अवधि में गांधी भवन में ही जरी-जरदोजी शिल्प प्रशिक्षण का आयोजन हुआ।

मास्टर ट्रेनर श्री फिरोज जहाद्वारा प्रतिभागियों को शादी-विवाह एवं त्योहारों के परिधानों, साड़ी बॉर्डर, दुपट्टों एवं क्लच पर्स आदि पर की जाने वाली जरी व जरदोजी कढ़ाई के उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।इस प्रशिक्षण में बाज़ार की मांग के अनुरूप डिज़ाइन विकसित करने पर विशेष बल दिया गया।

कढ़ाई शिल्प: स्वरोजगार की दिशा में सशक्त पहल

पुष्पा नगर, भोपाल में 20 जनवरी से 19 मार्च 2025 तक आयोजित कढ़ाई शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम मेंमास्टर ट्रेनर श्रीमती उजमा खानने हाथ व मशीन कढ़ाई की विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करवाया।कुशन कवर, बेडशीट, टेबल मैट, पर्दे आदि पर आकर्षक कढ़ाई डिज़ाइन बनाने की विधियाँ सिखाई गईं। प्रशिक्षण में उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाने की व्यावसायिक रणनीतियों की जानकारी भी शामिल थी।

प्रतिभागियों में उत्साह, आत्मनिर्भरता की ओर कदम

तीनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिल्पियों ने इसे अपने कौशल विकास एवं आजीविका के अवसर के रूप में देखा। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें डिज़ाइन, विपणन, और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर उत्पाद बेचने जैसी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मिलीं, जो उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी।

कार्यक्रम में विशिष्टजन रहे उपस्थित

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समापन अवसर पर हस्तशिल्प सेवा केंद्र, भोपाल के सहायक निदेशक श्री नरसिंह सैनी, विशेषज्ञ संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष राजपूत, एवं राज्य सहकारी संघ की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान की विशेष उपस्थिति रही।

भोपाल में कढ़ाई शिल्प पर कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा वृहंत हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के अंतर्गत डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला (कढ़ाई शिल्प) का आयोजन 20 जनवरी 2025 से 19 मार्च 2025 तक सीएफसी त्रिलंगा, शाहपुरा, भोपाल में किया गया।

कार्यशाला में प्रतिभागियों को पारंपरिक कढ़ाई शिल्प को आधुनिक डिजाइनों एवं तकनीकों के साथ जोड़ने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुभवी डिजाइनर सुश्री कामिनी मालवीय द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में महिलाओं एवं शिल्पकारों कोजरी, ज़रदोज़ी, मिरर वर्क, एप्लिक वर्क, कटवर्क आदि कढ़ाई शैलियों की बारीक जानकारी दी गई। साथ ही परिधानों की डिज़ाइनिंग, रंग संयोजन, नवीन सिलाई तकनीक, उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन की विधियों पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने कुर्तियाँ, दुपट्टे, पर्स, बेड शीट्स, तकिए के कवर आदि पर सुंदर कढ़ाई कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर स्थानीय हस्तशिल्प अधिकारियों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने कार्यशाला का निरीक्षण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

इस अवसर पर श्री नरसिंह सैनी, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र भोपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता की सराहना की और प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। यह कार्यशाला नारी सशक्तिकरण, पारंपरिक शिल्प संरक्षण एवं स्थानीय शिल्पकारों के आर्थिक उत्थान की दिशा में एक सराहनीय पहल रही।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।